



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28092020-222066
CG-DL-E-28092020-222066

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 265]
No. 265]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 28, 2020/ आश्विन 6, 1942
NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 28, 2020/ASVINA 6, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2020

मामला सं. एडी-(ओ आई) 21/2020

विषय: चीन, तथा यूएसए के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'परसल्फेट' के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

फा. सं. 6/25/2020-डीजीटीआर.—मै. कैलिबर कैमिकल्स प्रा. तथा मै. वीआर परसल्फेट्स (जिन्हें यहां आगे "आवेदक" भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष घरेलू उद्योग की ओर से एक आवेदन दायर किया है जिसमें चीन, तथा यूएसए (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "परसल्फेट्स", (जिसे आगे संबद्ध वस्तु या विशिष्ट रूप से विचाराधीन उत्पाद, या पीयूसी या भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में मूल पाटनरोधी शुल्क की मूल जांच की शुरूआत करने का अनुरोध किया गया है।

- आवेदकों ने, बाद में, जापान के खिलाफ इस आधार पर आवेदन वापस ले लिया कि बाद की अवधि (जनवरी-मार्च 2020) के लिए आयात की मात्रा में गिरावट आई थी और अप्रैल 2019-मार्च 2020 की अवधि के लिए डे मिनिसिस हो गया। तदनुसार, वर्तमान जांच की जा रही है चीन पीआर और संयुक्त राज्य अमेरिका से विषय वस्तुओं के आयात के खिलाफ पहल (बाद में "विषय देशों" के रूप में संदर्भित)।

3. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है और वास्तविक क्षति का खतरा है और उसने संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू करने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

4. विचाराधीन उत्पाद “पेरोक्सोसल्फेट्स” जिसे सामान्यतः “परसल्फेट्स” के नाम से जाना जाता है, है। परसल्फेट्स निकटस्थ संबंधित यौगिकों का एक समूह है। इसे अल्कली मेटल साल्ट के रूप में उत्पादित किया जाता है जिसमें अमोनियम परसल्फेट्स (एपीएस), पोटेशियम परसल्फेट्स (पीपीएस) तथा सोडियम परसल्फेट्स (एसपीएस) शामिल हैं।
5. इन परसल्फेट्स का रासायनिक सूत्र क्रमशः $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$, $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$, $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_8$ है। तीनों प्रकार के परसल्फेट के समान अंतिम प्रयोग हैं जो वस्त्र और रसायन उद्योग में प्रारंभिक और ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में प्रयुक्त हैं और एक को दूसरे से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। सभी तीन साल्ट एक हैं और समान उत्पाद हैं।
6. तीनों किस्मों की उत्पादन की लागत, बिक्री कीमत में भारी अंतर है। इन्हें विचाराधीन उत्पाद के तीन अलग-अलग ग्रेड माना जाता है। परसल्फेट्स का प्रयोग वस्त्र और रसायन उद्योग में प्रारंभिक और ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में होता है।
7. परसल्फेट्स को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 28 के उपशीर्ष 2833 40 तथा 283340 00 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, उक्त सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और जांच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

ख. समान वस्तु

8. आवेदकों ने दावा किया है कि भारत में पाटित की जा रही संबद्ध वस्तु घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के समान है। पाटित आयातों और घरेलू रूप से उत्पादित संबद्ध वस्तु के तकनीकी विनिर्देशनों, गुणवत्ता, कार्य या अंतिम प्रयोग में कोई अंतर नहीं है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं इसलिए नियमावली के अंतर्गत इन्हें समान वस्तु माना जाना चाहिए। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

ग. घरेलू उद्योग

9. यह आवेदन मै. कैलिबर कैमिकल्स प्रा. तथा मै. वीआर परसल्फेट्स द्वारा दायर किया गया है। आवेदकों ने दावा किया है कि न तो उन्होंने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक या किसी उत्पादक अथवा भारत में पीयूसी के किसी आयातक से संबंधित हैं। रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर यह नोट किया जाता है कि आवेदक नियम 2(ख) के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग है और आवेदन संबंधित नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार योग्यता संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

घ. कथित पाटन का आधार

चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य

10. आवेदकों ने प्रस्तुत किया है कि चीन पीआर को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और नियमों के अनुबंध 1 के पैराग्राफ -7 के संदर्भ में सामान्य मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए। आवेदकों ने तुर्की को चीन पीआर के लिए उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था तीसरे देश के रूप में सुझाया है और तुर्की में कीमत पर विचार किया है और सामान्य मूल्य के आधार पर तुर्की से निर्यात करता है।
11. भारत में उत्पादन की लागत को ध्यान में रखते हुए, भारत में देय कीमत के आधार पर आवेदकों ने चीन के लिए सामान्य मूल्य भी प्रदान किया है, बेचने के अलावा, सामान्य खर्च और उचित लाभ। वर्तमान दीक्षा के उद्देश्य से ही इसे उपयुक्त माना गया है। चीन पीआर के लिए आवेदकों द्वारा दावा किए गए सामान्य मूल्य के पर्याप्त सबूत हैं।

यूएसए के लिए सामान्य मूल्य

12. आवेदकों ने प्रस्तुत किया है कि उन्होंने यूएसए के घरेलू बाजार में संबंधित उत्पाद की कीमत के प्रमाण प्राप्त करने के प्रयास किए हैं। हालाँकि, सार्वजनिक डोमेन में ऐसी कीमत उपलब्ध नहीं थी। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए सामान्य मूल्य संयुक्त राज्य अमेरिका में विषय वस्तुओं के आयात के आधार पर निर्धारित किया गया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में आयात मूल्य को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित मूल्य है।
13. संबद्ध वस्तु के विभिन्न ग्रेडों की कीमत और लागत में भारी अंतर को देखते हुए प्रत्येक ग्रेड अर्थात् अमोनियम परसल्फेट्स (एपीएस), पोटेशियम परसल्फेट्स (पीपीएस) तथा सोडियम परसल्फेट्स (एसपीएस) के लिए सामान्य मूल्य प्रत्येक संबद्ध देश हेतु अलग-अलग निर्धारित किया गया है।

ड. निर्यात कीमत

14. संबद्ध देशों के लिए निर्यात कीमत का परिकलन वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) से प्राप्त सौदावार आयात आंकड़ों के आधार पर किया है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, संभलाई प्रभार, पत्तन व्यय, बैंक प्रभार और वैट रिफंड (केवल चीन हेतु) के लिए कीमत समायोजन किए गए हैं।

च. पाटन मार्जिन

15. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखाना द्वार स्तर पर तुलना की गई है जिससे प्रथम दृष्टया संबद्ध देशों से पीयूसी के संबंध में पाटन मार्जिन के न्यूनतम सीमा से अधिक और काफी अधिक होने का पता चलता है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पीयूसी का पाटन किया जा रहा है।

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध

16. आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सूचना पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन हेतु विचार किया गया है। आवेदक ने समग्र रूप से और भारत में कुल आयातों, उत्पादन और खपत की दृष्टि से पाटित आयातों की बढ़ी हुई मात्रा, कीमत कटौती, कीमत ह्रास और घरेलू उद्योग के कीमत न्यूनीकरण के रूप में कथित पाटन के परिणामस्वरूप क्षति होने के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। आवेदक ने दावा किया है कि उनका कार्य निष्पादन घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और क्षति रहित कीमत से कम कीमत पर संबद्ध वस्तु के आयातों में वृद्धि के परिणामस्वरूप मालसूची, लाभ, और आरओआई के संबंध में बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।
17. आवेदकों ने यह भी दावा किया है कि आयातों से पीओआई में आयातों में भारी वृद्धि पर विचार करते हुए वास्तविक क्षति के खतरे, भारी सकारात्मक कीमत कटौती, संबद्ध देशों में अत्यधिक अतिरिक्त क्षमताओं, संबद्ध देशों में उत्पादकों का अत्यधिक निर्यातोन्मुख होना, कम अवधि में उत्पादन बढ़ाने की क्षमता पर विचार करते हुए वास्तविक क्षति का खतरा है।
18. विषय देशों से विषय वस्तुओं के आयात को फेंके जाने से घरेलू उद्योग को चोट लगने का पर्याप्त प्रथम दृष्टया प्रमाण है।

ज. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

19. घरेलू उद्योग के द्वारा या उसकी ओर विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद और नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी, जांच की शुरुआत करते हैं।

झ. संबद्ध देश

20. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन, और यूएसए हैं।

ञ. जांच की अवधि (पीओआई)

21. आवेदकों ने जांच अवधि (पीओआई) के लिए अप्रैल 2019-दिसंबर, 2019 (9 माह) का प्रस्ताव किया है। क्षति जांच अवधि में 2016 - 2017, 2017-2018, 2018 -2019 और पीओआई की अवधियों पर विचार किया गया है। नियम 22(3) में संशोधन के स्पष्टीकरण को देखते हुए जांच की अवधि (पीओआई) अप्रैल 2019- मार्च, 2020 (12 माह) के रूप में प्रस्तावित है तथा क्षति अवधि अप्रैल 2016-मार्च, 2017, अप्रैल 2017- मार्च, 2018, अप्रैल 2018- मार्च 2019 और पीओआई की अवधियां शामिल होंगी।

ट. प्रक्रिया

22. नियमावली के नियम 6 में यथाप्रदत्त सिद्धांतों का वर्तमान जांच में पालन किया जाएगा।

ठ. सूचना प्रस्तुत करना

23. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पत्तों adg13-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, dir12-dgtr@gov.in और dd15-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए।
24. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकारों, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।
25. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
26. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
27. इच्छुक पार्टियों को इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन जानकारी के लिए नामित प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट <http://www.dgtr.gov.in> पर नियमित निगरानी रखने की सलाह दी जाती है।

ड. समय-सीमा

28. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर ऊपर उल्लिखित ई-मेल पत्तों पर ई-मेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। तथापि यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने की तारीख या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
29. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

ढ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

30. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका एक अगोपनीय अंश साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। इसका पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है।

31. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को गोपनीयता के दावे के मामले में दो अलग-अलग सैट प्रस्तुत करना अपेक्षित है। गोपनीय रूप में चिह्नित एक सैट (शीर्षक, पृष्ठ सं., सूची आदि सहित) और अगोपनीय रूप में चिह्नित दूसरा सैट (शीर्षक, पृष्ठ सं., सूची आदि सहित)।
32. "गोपनीय "या" अगोपनीय "अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
33. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
34. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।
35. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
36. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
37. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ण. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

38. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

त. असहयोग

39. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

बि बि स्वैन, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 2020

Case No. (AD-OI – 21/2020)

Subject : Initiation of Anti-Dumping Investigation concerning imports of “Persulphates” originating in or exported from China PR and USA.

F. No. 6/25/2020-DGTR.—M/s Calibre Chemicals Pvt and M/s VR Persulphates, (hereinafter also referred to as “Applicants”) have filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Rules”) for Original Investigation of Anti-dumping Duty concerning imports of “Persulphates” (hereinafter also referred to as “subject goods” or specifically as “product under consideration” or “PUC”, originating in or exported from china, and U.S.A. (hereinafter also referred to as the “subject countries”).

2. Applicants, subsequently, withdrew the application against Japan on the ground that the volume of import for subsequent period (Jan-March 2020) had declined and became *de minimis* for the period April 2019-March 2020. Accordingly, the present investigation is being initiated against imports of the subject goods from China PR and USA (hereinafter referred as “subject countries”).
3. The Applicants have alleged material injury and threat of material injury to the Domestic Industry due to dumped imports from the subject countries and have requested for imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries.

A. Product under consideration

4. The product under consideration is ‘Peroxosulphates’ commonly known as ‘Persulphates’. Persulphates are a group of closely related compounds. These are produced as Alkali Metal salts which include Ammonium Persulphates (APS), Potassium Persulphates (PPS) and Sodium Persulphates (SPS).
5. The Chemical Formula of these Persulphates are, respectively, (NH₄)₂S₂O₈, K₂S₂O₈, Na₂S₂O₈. The three types of Persulphates have the same end-uses as an initiator and oxidizing agent in the textile and chemical industries and one can be substituted for another. All three salts are one and same product.
6. The cost of production, selling price of three types varies significantly. These are considered as three different grades of the product under consideration. Persulphates is used as an initiator and oxidizing agent in the textile and chemical industries.
7. Persulphates is classified in Chapter 28 of the Customs Tariff Act, 1975 under subheading 2833 40 and under subheading 283340 00. However, the said customs classifications are only indicative, and the same are not binding on the scope of the investigation.

B. Like Article

8. The Applicant has claimed that that there is no known difference between the subject goods exported from the subject countries and that produced by the domestic industry. Subject goods produced by the domestic industry and PUC imported from subject countries are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers use the two interchangeably. The Applicant has further claimed that the two are technically and commercially substitutable and, hence, should be treated as like article under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the Applicant in India are being treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject countries.

C. Domestic Industry

9. The Application has been filed by M/s Calibre Chemicals Pvt and M/s VR Persulphates. The Applicants have claimed that they has neither imported the subject goods from the subject countries nor are related to any exporter or producer of subject goods in the subject countries or any importer of the PUC in India. On the basis of information on record, it is noted that the Applicants constitute eligible domestic industry in terms of Rule 2 (b), and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules supra.

D. Basis of Alleged Dumping**Normal Value for China PR**

10. The Applicants have submitted that China PR should be considered as a non-market economy and the normal value should be determined in terms of paragraph-7 of Annexure I of the Rules. The applicants have suggested Turkey as appropriate market economy third country for China PR and has considered price into Turkey and exports from Turkey as the basis of normal value.
11. Applicants have also provided normal value for China PR on the basis of the price actually payable in India by considering cost of production in India, after addition for selling, general & administrative expenses and reasonable profits. The same has been considered appropriate for the purpose of present initiation. There is sufficient evidence of the normal value claimed by the Applicants for China PR.

Normal value for USA

12. The applicants have submitted that they made efforts to get evidence of price of product concerned in the domestic market of USA. However, such price was not available in public domain. The normal value for USA has been determined based on the imports of subject goods into USA considering the import price into USA as the consumption price prevailing in USA.
13. Owing to significant difference in price and cost of different grades of subject goods, normal value for each grade, i.e., Ammonium Persulphates (APS), Potassium Persulphates (PPS) and Sodium Persulphates (SPS) has been determined separately for each subject country.

E. Export price

14. The export price for the subject countries has been computed based on Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) transaction-wise import data. Price adjustments have been made on account of ocean freight, marine insurance, commission, handling charges, port expenses, bank charges, and VAT refund (only for China).

F. Dumping Margin

15. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which *prima facie* shows dumping margin, which is above the de-minimis, and is significant in respect of the PUC from the subject countries. There is sufficient *prima facie* evidence that the PUC from subject countries are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject countries.

G. Injury and Causal Link

16. Information furnished by the Applicants have been considered for assessment of injury to the domestic industry. The Applicants have furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms, and in relation to production and consumption in India, price undercutting, price suppression and depression on the domestic industry. The Applicants have claimed that its performance has been adversely impacted in respect of increase in inventories, and decline in profits, and ROI, as a result of increase in imports of subject goods at a price below selling price and non-injurious price for the domestic industry.
17. The applicants have also claimed that imports are causing threat of material injury, considering significant increase in imports in the POI, significant positive price undercutting, significant surplus capacities in subject countries, high export orientation of producers in subject countries, ability to scale up production in short span.
18. There is sufficient *prima facie* evidence of injury being caused to the domestic industry by dumped imports of subject goods from the subject countries.

H. Initiation of Anti-Dumping Investigation

19. On the basis of the duly substantiated written application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the *prima facie* evidence submitted by the domestic industry, about dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates investigation to determine the existence, degree and effect of alleged dumping in respect of the product under consideration originating and exported from the subject countries and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

I. Subject Countries

20. The subject countries in the present investigation are China PR, and USA.

J. Period of Investigation

21. The applicants have proposed period of investigation (POI) as April 2019-December 2019 (9 months). The injury investigation period has been considered as the periods 2016–2017, 2017-2018, 2018-19 and POI. In view of explanation to amended Rule 22 (3), the period of investigation (POI) is being proposed as April 2019- March 2020 (12 months) and the injury period will cover the periods April 2016- March 2017, April 2017- March 2018, April 2018- March 2019 and the POI.

K. Procedure

22. Principles as given in Rule 6 of the Rules will be followed for the present investigation.

L. Submission of Information

23. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg13-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, dir12-dgtr@gov.in and dd15-dgtr@gov.in.
24. The known producers/exporters in the subject countries, their Governments through their Embassies in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
25. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.
26. Any party making any confidential submission before the Authority is requested to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
27. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Designated Authority <http://www.dgtr.gov.in> for any updated information with respect to this investigation.

M. Time Limit

28. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority via email at the email addresses mentioned above within thirty days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said sub rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
29. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

N. Submission of information on confidential basis

30. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.

31. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof: one set marked as Confidential (with title, number of pages, index, etc.), and the other set marked as Non-Confidential (with title, number of pages, index, etc.).
32. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
33. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
34. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
35. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
36. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
37. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information

O. Inspection of Public File

38. In terms of Rule 6(7) of the Anti-Dumping Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

P. Non-cooperation

39. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

B. B. SWAIN, Spl. Secy. & Designated Authority